दैनिक
नया तेवर, नया कलेवर
यशोभूमि

भू-राजनीतिक तनाव ने बढ़ाई कृषि निर्यातकों की चिंता

यशोभूमि/प्रतिनिधि

मुंबई। दुनिया भर में बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव और समुद्री व्यापार मार्गों में आ रही बाधाओं ने भारतीय कृषि और डेयरी निर्यातकों की चिंता बढ़ा दी है। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर मुंबई और ऑल इंडिया एसोसिएशन ऑफ इंडस्ट्रीज ने आशंका जताई है कि रसद की बढ़ती लागत और देरी से खराब होने वाले उत्पादों के व्यापार पर बुरा असर पड़ रहा है। डब्ल्यूटीसी मुंबई के चेयरमैन और एआईएआई के अध्यक्ष डॉ. विजय कलंत्री ने कहा, भारत का कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य निर्यात सालाना 50 बिलियन डॉलर से अधिक है, जबकि डेयरी निर्यात लगभग 500 मिलियन डॉलर है। हालिया संकट के कारण कुछ मार्गों पर माल ढुलाई और लॉजिस्टिक्स लागत में 40% या उससे अधिक की वृद्धि हुई है।

डॉ. कलंत्री ने की सरकार से हस्तक्षेप की मांग

डॉ. कलंत्री ने जोर देकर कहा कि फल, सब्जियां और डेयरी जैसे उत्पाद समय के प्रति बेहद संवेदनशील होते हैं। शिपिंग में देरी न केवल उत्पाद की गुणवत्ता और शेल्फ-लाइफ को प्रभावित करती है, बल्कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में भारतीय निर्यातकों की प्रतिस्पर्धात्मकता और मार्जिन को भी कम कर देती है। एमएसएमई निर्यातकों के हितों की रक्षा के लिए डब्ल्यूटीसी और एआईएआई ने सरकार से हस्तक्षेप की मांग की है। डॉ. कलंत्री ने सुझाव दिया कि सरकार को खराब होने वाली वस्तुओं के लिए विशेष लॉजिस्टिक्स और फ्रेट सब्सिडी के साथ-साथ निर्यात ऋण पर ब्याज सब्सिडी जैसे लक्षित उपाय करने चाहिए।

मॉरीशस देगा सुरक्षित प्लेटफॉर्म

भारत और मॉरीशस के बीच द्विपक्षीय व्यापार और निवेश संबंधों को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के उद्देश्य से वर्ल्ड ट्रेड सेंटर मुंबई में एक विशेष बैठक का आयोजन किया गया। इस अवसर पर भारत में मॉरीशस की उच्चायुक्त शीलाबाई बापू ने भारतीय निवेशकों को मॉरीशस में निवेश के लिए आमंत्रित किया। उन्होंने कहा कि भारतीय कंपनियां मॉरीशस का उपयोग इन वैश्विक बाजारों तक पहुंचने के लिए एक महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म के रूप में कर सकती हैं। श्रीमती बापू ने कहा कि मॉरीशस केवल एक पर्यटन स्थल नहीं, बल्कि एक सुरक्षित और संधि-अनुरूप अधिकार क्षेत्र है। उन्होंने कहा, मॉरीशस के यूरोपीय संघ, ब्रिटेन, चीन और यूएई जैसे प्रमुख देशों के साथ मजबूत द्विपक्षीय समझौते हैं।